

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 2175 / 2023

विवेक हजेला, आयु 55 वर्ष, पिता- विश्वेश्वर प्रसाद, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के निर्माण और खनन मशीनरी व्यवसाय (सीएमबी) में कार्यकारी उपाध्यक्ष, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी -पंजीकृत कार्यालय एलएंडटी हाउस, एन.एम. मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, डाकघर बैलार्ड एस्टेट, थाना- बैलार्ड एस्टेट, जिला मुंबई 400001 तथा 88/2, द्वितीय तल, द्वितीय क्रॉस, रामकृष्ण गार्डन, गौरी अपार्टमेंट के पीछे, न्यू बीईएल रोड, आरएमवी द्वितीय स्टेज, डॉलर कॉलोनी, बेंगलोर, कर्नाटक 560054।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. नवीन कुमार अग्रवाल, पिता- स्वर्गीय हीरालाल अग्रवाल, 3/6 एचएस टॉवर, एल रोड, डाकघर बिष्टुपुर, थाना बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, स्थायी निवाश -193/3 सुधा भवन, न्यू सीताराम डेरा, डाकघर न्यू सीताराम डेरा, थाना, न्यू सीताराम डेरा, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

... विपक्षी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री विकास पांडे, अधिवक्ता

श्री दीपक कुमार। सिन्हा, अधिवक्ता

श्री जनक कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

श्री संजय कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

सुश्री दीक्षा द्विवेदी, अधिवक्ता

राज्य के लिए:

सुश्री कुमारी रश्मि, अपर पी.पी.

ओ.पी. संख्या 2 के लिए:

श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:-दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है बिष्टुपुर थाना से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन को रद्द करने की प्रार्थना के साथ। भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला संख्या 144/2023 पंजीकृत है जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतरिम आवेदन संख्या 10973/2023 की ओर आकर्षित करते हैं, जो याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2/सूचनाकर्ता के जोड़ीदार के हलफनामे द्वारा समर्थित है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 ने समझौता ज्ञापन दिनांक 15.09.2023 के तहत बिना किसी बल, जबरदस्ती, दबाव, धमकी या प्रलोभन के मामले में समझौता कर लिया है और पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौते के मद्देनजर विपक्षी संख्या 2 उक्त बिष्टुपुर थाना केस नं. 144/2023. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है और कुछ गलतफहमी के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। अपने प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2014) 6 एससीसी 466 पैराग्राफ-29 में रिपोर्ट**

किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें निम्नलिखित लिखा है:

“29. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हैं और निर्धारित करते हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को पर्याप्त उपचार देने और समझौते को स्वीकार करते हुए और कार्यवाही को रद्द करते हुए या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में निर्देशित होगा:

29.1. संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को शमन करने की न्यायालय में निहित शक्ति से अलग किया जाना चाहिए। निस्संदेह, संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, यहां तक कि उन मामलों में भी जो शमनीय नहीं हैं, जहां पक्षों ने आपस में मामले का निपटारा कर लिया है। हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

29.2. जब पक्षकार समझौता कर लेते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगा:

(i) न्याय के उद्देश्य, या

(ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपर्युक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर राय बनानी होती है।

29.3. ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोगों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून

के तहत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

29.4. दूसरी ओर, वे आपराधिक मामले जो मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के हैं, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तब रद्द किया जाना चाहिए जब पक्षकार अपने बीच अपने सभी विवादों को सुलझा लें।

29.5. अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को यह जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना पड़ेगा और आपराधिक मामलों को रद्द न करने से उसके साथ बहुत अधिक अन्याय होगा।

29.6. धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। हालांकि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपना निर्णय नहीं लेगा क्योंकि एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि क्या धारा 307 आईपीसी को शामिल करना इसके लिए है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित करने में मदद करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, चाहे ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक भागों पर लगी हो, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि के आधार पर जाना होगा। पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकती हैं। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। पहले मामले में यह समझौता स्वीकार करने से इनकार कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है जबकि दूसरे मामले

में उच्च न्यायालय के लिए पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध को कम करने की दलील को स्वीकार करना स्वीकार्य होगा। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप उनके बीच सामंजस्य स्थापित होगा जो उनके भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकता है।

29.7. संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, यह तय करते समय, निपटान का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मामले जिनमें कथित अपराध के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदारता दिखा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर जांच अभी भी जारी है और यहां तक कि आरोप-पत्र भी दायर नहीं किया गया है। इसी तरह, वे मामले जहां आरोप तय हो गया है लेकिन सबूत अभी शुरू नहीं हुए हैं या सबूत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर वर्णित परिस्थितियों/सामग्री का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी तरह, उन मामलों में जहां ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलिय चरण में है, पक्षों के बीच मात्र समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप अपराधी को बरी कर दिया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। यहां धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप साबित हो चुका है और जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि पहले ही दर्ज की जा चुकी है और इसलिए ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए गए दोषी को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। (जोर दिया गया) अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिष्टुपुर पी.एस. केस

संख्या 144/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त कर दिया जाए। 4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर, राज्य को बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः यह निवेदन किया जाता है कि बिष्टुपुर पी.एस. मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त कर दिया जाए। (जोर दिया गया)

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पक्षों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर राज्य को बिष्टुपुर पी.एस. मामला संख्या 144/2023 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।
5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परबतभाई आहिर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में रिपोर्ट किए गए मामले में, पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार माना गया है:-

“11. धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान से शुरू की गई है। यह कानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को एक उच्च न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए बचाता है जो (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303: (2012) 4 एस.सी.सी.

(सिविल) 1188: (2013) 1 एस.सी.सी. (क्रि) 160: (2012) 2 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करते समय विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफ.आई.आर. या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय को जिन बातों पर विचार करना चाहिए, वे हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 342-43, पैरा 61)

“61. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध उचित रूप से निरस्त नहीं किए जा सकते, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन आपराधिक मामले, जिनमें मुख्य रूप से सिविल मामले शामिल हैं, निरस्तीकरण के लिए अलग आधार पर आते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल,

साझेदारी या ऐसे ही अन्य लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित के विरुद्ध होगा या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। (जोर दिया गया)”

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध न तो जघन्य अपराध हैं और न ही मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध है, बल्कि यह दोनों पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।
7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता हो जाने के कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ बहुत अन्याय होगा।
8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, बिष्टुपुर पी.एस. केस संख्या 144/2023 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक अभियोजन, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।
10. परिणामस्वरूप, यह सीआर.एम.पी. स्वीकृत की जाती है।
11. तत्काल सीआर.एम.पी. के निपटान के मद्देनजर, आई.ए. संख्या 10973/2023 तदनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 20 दिसंबर, 2023

एफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।